of important crop plants sustainability of farming/cropping system, bio-systematics integrated nutrient management etc. to promote new technology.

(b) Substantially high allocation of Rs. 215.19 crore has been made for the Institute by the ICAR for the VIII Plan period (1992—97).

(c) Eleven research assignments with foreign collaboration have been undertaken. These relate to phytotron facility, post harvest technology, seeds, varietal improvement, biotechnology integrated pest management etc.

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण-नीति का पालन न किया जाना

*369. **श्री मूल चन्द मीणा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विश्व-विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण-नीति का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के पालनार्थ सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार इस आरक्षण नीति का पालन न करने वाले विश्व-विद्यालयों को दी जा रही सहायता-अनुदान राशि पर रोक लगाने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए समय-समय पर यथा-घोषित आरक्षण नीति को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि वे सरकार की आरक्षण नीति का पालन करें। तथापि, विश्वविद्यालयों का स्वायत्त स्वरूप होने के कारण, उनका निर्णय लेने का अपना तंत्र है और कुछ विश्वविद्यालयों में आरक्षण सरकार की आरक्षण-नीति के अंतर्गत अपेक्षित सीमा तक नहीं हुआ है। इस मामले की उपयुक्त उपचारी कार्रवाई के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को निधियां प्रदान की जाती है, जो आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों से आग्रह करता रहा है।

Release of Funds to Mumbai Mahanagar Palika

*370. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra has not transferred the approved aid of Rs. 100 crores sanctioned by the Central Government during 1985 to Mumbai Mahanagar Palika; if so, the reasons therefor;

(b) whether Government propose to allocate any ad-hoc grant to the satellite Mahanagar Palika like Thane, Kalyan, Navi Mumbai which are facing indentical problems as that of Mumbai Mahanagar Palika; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) A special grant of Rs. 100 crores was sanctioned in 1987 by the Government of India to the Government of Maharashtra for tackling the problem of slums and housing in Bombay. The projects are to be implemented by various agencies including Bombay Municipal Corporation (BMC). Out of Rs. 100 crores, Rs. 88 crores have been released upto 31st March, 1992 to the Government of Maharashtra for distribution to the implementing agencies on the basis of the progress of works.

(b) and (c) No, Sir. 'Urban Development' is a State subject and the Ministry of Urban Development in the Government of India plays only a nodal role. There are no discretionary funds with the Government of India for giving such grants to any city. The State Governments would have to formulate necessary development projects and get them included in the annual plans in

consultation with Union Planning Commission.

Development of townships in Delhi Metropolitan Areas

*371. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any proposal is under Government's consideration to develop new townships alongside existing towns in Delhi Metropolitan areas;

(b) if so, the location thereof; and

(c) by when the above work is likely to start?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Report on fire Accidents in Delhi

372. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of the report received by Government on the fire accidents that engulfed various Government and public buildings in Delhi during the last three years;

(b) whether the CPWD and DFS have not adopted the latest methods to prvent recurrence of fire accidents;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) what are the existing ways and means to fight the fire accidents?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) During the last three years (period ending March, 1992) 6 fire accidents of Government and other public premises were reported to Government by the Delhi Fire Service.

(b) Available facilities are utilised.

(c) Does not arise.

(d) The mandatory provisions for prevention are being implemented. The Delhi Fire Service has 30 Fire Stations established all over Delhi to extinguish fires.

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाने के लिये राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

*373. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नये केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में जिन-जिन राज्यों और जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनका ब्यौरा क्या है तथा कहां-कहां उन्हें खोलने का प्रस्ताव किया गया है,

(ख) क्या उपर्युक्त प्रस्तावों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान देश में कहीं कोई केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले गए हैं, और

(ग) वे कौन-कौन से स्थान है जहां इन विद्यालयों को खोले जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) नवोदय विद्यालय राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त औपचारिक प्रस्तावों या सिफारिशों के आधार पर ही समय-समय पर विभिन्न जगहों से आए सुझावों को ध्यान में रखते हुए खोले जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालय प्रयोक्ता एजेन्सियों की मांगों के आधार पर खोले जाते हैं। इन विद्यालयों को खोलने के लिए भौतिक और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति सामान्य पूर्वापेक्षाएं होती हैं।

(ख) और (ग) चालू वर्ष में कोई नया केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार करने तथा जगहों का निरीक्षण करने के बाद इस वर्ष के दौरान 42 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। ब्यौरे सभापटल पर प्रस्तुत विवरण में दर्शाये गए हैं।

वर्ष 1992-93 के दौरान खोले गए नवोदय विद्यालय

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	जिला	स्थान
1	2	3	4
1.	मध्य प्रदेश	1. मंडला	पद्मी
		2. विदिशा	शमशाबाद
		3. उज्जैन	घट्टिया